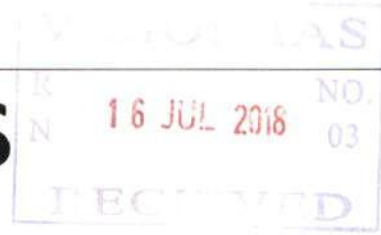




VISION IAS

www.visionias.in



GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1068)

Name of Candidate	Sunil Kumar Dhanwanta		
Medium Hindi/Eng.	Hindi	Registration Number	109506
Center	KB	Date	16/07/18

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

Signature of Examiner

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
2. There are TWENTY questions printed in ENGLISH.
3. All questions are compulsory.
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

M-1/4, Plot No-A-12/13, 1st Floor, Ansal Building, Dr. Vidya Sagar Homeopathic Clinic, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

Handwritten signature

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

1. There are many challenges in sustainably scaling up renewable energy in India. Analyse. Also, discuss what can be done to address these challenges.
(150 words) 10

भारत ने अपने 'INDC (Intended
Nationally determined contribution)' के तहत
2030 तक कुल ऊर्जा का 40% नवीकरणीय स्रोतों
से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

परन्तु इन लक्ष्य को प्राप्त करने
के नवीकरणीय ऊर्जा के सतत विकास के क्षेत्र
में निम्नलिखित चुनौतियाँ विद्यमान हैं-

- (क) उन्नत तकनीक व प्रौद्योगिकी का अभाव
- (ख) सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा की तकनीकों का
महंगा होना
- (ग) खेत की कमी
- (घ) भारत के समग्र सामाजिक व आर्थिक विकास
की चुनौति
- (च) भारत द्वारा इस क्षेत्र में शोध व अनुसंधान
की निम्न स्थिति

प्रमुख उपाय-

- (क) ग्रीन बॉण्ड के द्वारा वित्त प्राप्त करने पर बल देना
- (ख) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा विकसित देशों से उपयुक्त तकनीक प्राप्त करना
- (ग) ऐतिहासिक समझौते व ग्रीन क्लाइमेट फंड के सफल क्रियान्वयन हेतु अंतर्राष्ट्रीय मंत्रिकय विकसित करना
- (घ) इस क्षेत्र में शोध व नवाचार को बढ़ाना

उत्तर

चूंकि भारत एक विकसित देश है तथा इसके समस्त औद्योगिक व सामाजिक विकास की चुनौतियां विद्यमान हैं अतः भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा इस समस्या के समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए।

2. The policies and indicators introduced by the government, in recent times, to finance urban development in India are key in addressing the existing challenges. Discuss with special reference to municipal bonds.

(150 words) 10

भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 31% भाग शहरों में निवास करता है तथा शहर भारत की GDP में लगभग 70% योगदान देते हैं। अतः शहरों का विकास देश के विकास हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

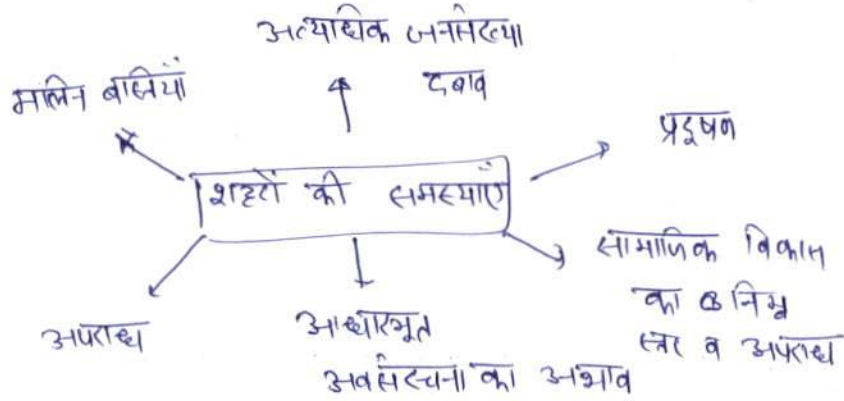
भारत सरकार की नीतियाँ एवं संकेतक

- (क) नगरपालिका बॉन्ड जारी करने संबंधी सेवा के दिशा-निर्देश
- (ख) क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों जैसे क्रिफिल द्वारा शहरों की रेटिंग जारी करना ताकि उनकी निवेश आकर्षण क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके
- (ग) स्वच्छ भारत अभियान के तहत 'स्वच्छ सर्वेक्षण'

नगरपालिका बॉन्ड -

शहरों की स्थानीय गणिकाओं द्वारा वित्तपोषण

के लिए इन बॉण्ड्स को जारी किया जाता है।



इन विकल्पों द्वारा इन बॉण्ड्स को अनेक दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए जारी कर धन प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि इन विकल्पों के पास वित्त के सीमित संसाधन उपलब्ध होते हैं अतः इन बॉण्ड्स के द्वारा शहरी विकास में तीव्रता नहीं जा सकती है।

3. With a number of issues continuing to be a roadblock, a large section of India's rural population is still 'financially excluded'. Discuss. Analyse how these issues can be addressed and the measures taken by the government and RBI recently in this regard. (150 words) 10

समाज के हाशिए पर स्थित वर्ग तक वित्तीय सेवाओं की पहुँच को वित्तीय समावेशन की संज्ञा दी जाती है। नियंत्रित मोड समिति ने इस संबन्ध में अपने सुझाव दिए हैं।

वित्तीय समावेशन के समक्ष चुनौतियाँ

- (i) देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की उपस्थिति का निम्न स्तर
- (ii) देश की अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या में वित्तीय साक्षरता का निम्न स्तर
- (iii) बैंकों द्वारा इस क्षेत्र में कम तकनीकी-दिखाना तथा सरकारी योजनाओं के उचित कार्यान्वयन का अभाव

समाधान के उपाय -

- (i) बैंकों की शाखाओं, बैंक मित्रों, 'मोबाइल बैंक ATM'

इन्हारे के माध्यम से देश के 50-55 ज के क्षेत्र में बैंक सेवाओं की पुनर्निर्माण करना

(ख) पेस्ट पेमेंट बैंक व लघु वित्त बैंकों की स्थापना

(ग) विनीप साक्षरता व जागरूकता में बढ़ि करना

सरकार के उपाय -

(i) प्रधानमंत्री जनकल्याण योजना

(ii) विनीप साक्षरता अभियान

(iii) भीम एप व आधार भुगतान की प्रोत्साहन

(iv) साक्षरता व पेशा का बैंक खातों से लिंकिंग

RBI के उपाय -

(i) पेमेंट बैंकों की स्थापना संबंधी दिशा-निर्देश

(ii) 'टाइड लेवल एपीएम' की स्थापना की मंजूरी

इस प्रकार उपरोक्त उपायों के द्वारा विनीप समावेश को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है।

4. What do you understand by the term 'Environmental Accounting'? Discussing the rationale behind introducing environmental accounting, highlight its status in India. (150 words) 10

विकास के कार्यक्रमों के द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों का लेखा-जोखा करना ही पर्यावरण लेखांकन कहलाता है।

- इसमें पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों की आर्थिक कीमत की गणना की जाती है।
- अनेक परियोजनाओं के कारण होने वाली पर्यावरणीय क्षति की गणना कर उसके प्रोजेक्ट मूल्य में शामिल किया जाता है।

पर्यावरणीय लेखांकन का औचित्य

- (i) पर्यावरणीय क्षति का आर्थिक मूल्यांकन ताबे उसी क्षतिपूर्ति के लिए करम उठाया जा सके।
- (ii) लोगों व सरकार को पर्यावरण के संबन्ध में जागरूक बनाया जा सके।
- (iii) क्षति की गणना करते के पश्चात् शमन उपायों (mitigation measures) पर चर्चा की जा सके।

भारत में स्थिति-

- (i) पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम, 1986 में इसकी
वैद्य (Legal) व्यवस्था की गई
- (ii) 1993 में एक अधिसूचना के द्वारा अनेक
परिमेयनाओं जैसे विद्युत, कोयला, परमाणु कर्ना
इत्यादि के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन
की व्यवस्था

हालांकि सरकारी विभागों में अष्टाचार व
धीमी आर्थिक प्रक्रिया के कारण उपर्युक्त प्रावधानों
को उचित ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है।
इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा एवं समतल विकास के
लिए पर्यावरणीय लेखांकन को समुचित रूप
से लागू करने की आवश्यकता है।

5. While access to irrigation is important, efficiency of water use is equally, if not more, crucial. Examine. (150 words) 10

भारत का लगभग 70% क्षेत्र शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों के अन्तर्गत आता है। इसी के साथ ही मानसून की अनिश्चितता के कारण पानी की कमी का सामना करना पड़ता है।

इसलिए भारत में सिंचाई का अत्यधिक महत्व है। इसी के साथ भारत की लगभग 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है।

इसलिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने व आर्थिक विकास के लिए सिंचाई का कृषि में महत्वपूर्ण स्थान है।

सिंचाई क्षेत्र की समस्याएँ

- (i) बाढ़ सिंचाई के कारण पानी का बर्बाद होना तथा लवणता की समस्या
- (ii) पानी के आधिक्य के क्षेत्रों से जल को -यूनता वाले क्षेत्रों में पहुँचाने के लिए आवश्यक अवसंरचना की कमी

शुभललल ँल ँडुडुडु डकुल कु डुडुडु डकुल
ऑललल ।

डुडुडु डुडुडु

- (i) डलड डलडलल कु डलड डुडुडु डुडुडु डलडलल
डुडुडु डलडलल कु डलडलललल
- (ii) डुडुडु कु डलड कु डलडलललल कु डलडलल डल
डलडलल कु डलडलल डलडलल
- (iii) 'डुडुडुडुडु' कु डलडललल डल डलड डल डलडलल
डलडललल
- (iv) डलड कु डलडललललल डलड डलडललललल डलडलल
- (v) डुडुडु, डलडलल डलडललल कु डलडललल

डलड डलडलल डलड डलडलललल कु
डलडललल डल डलड डलडललल कु डलडललल डलडललल
कु डलडललललल डलडलल डलडललल डलडललल

6. For a holistic approach to disaster risk reduction, there is a need to mainstream indigenous traditional knowledge and link it with modern technologies. Analyse. (150 words) 10

अनेक अध्ययनों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सन् २००४ की सुनामी के दौरान अण्डमान निकोबार द्वीप समूह पर बसने वाली अनेक जनजातियों ने अपने परंपरागत ज्ञान के द्वारा इसका सामना करने में सफलता प्राप्त की थी।

आपदा प्रबंधन के अन्तर्गत आपदा जोखिम-सूनीकरण एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसके अन्तर्गत ऐसे उपायों को शामिल किया जाता है जिनके द्वारा समाज व अर्थव्यवस्था पर आपदा के प्रभावों को न्यूनतम किया जा सके।

परंपरागत ज्ञान के पक्ष में तर्क

- (i) यह स्थानीय रूप में उपलब्ध होता है तथा आपदा के दौरान पुनर्न कर्म में लया जा सकता है
- (ii) यह कई कई बार दुर्गम क्षेत्रों में सरकारी

तंत्र का पहुँचना कठिन होता है और वहाँ इस
ज्ञान का प्रयोग उपयोगी साबित हो सकता है।

विपस में तंत्र

- (i) यह ज्ञान लोगों के अनुभव पर आधारित होता
है और इसके द्वारा भविष्य की आपदाओं
का पूर्वानुमान सटीक रूप से करना संभव
नहीं है।
- (ii) इसमें ख़तरों को कम किया जा सकता है। परन्तु
तकनीक के स्तरेमाल से इसे -यूनलूम किया
जा सकता है।

अतः हमें परम्परागत ज्ञान तथा तकनीकी
ज्ञान के संश्लेषण की आवश्यकता है।

7. What do you understand by food irradiation? Highlighting some of its unique applications, examine its relevance for India. (150 words) 10

विभिन्न विकिरणों जैसे पराबैंगनी विकिरणों के प्रयोग से खाद्य पदार्थों में उपलब्ध हानिकारक जीवाणुओं व विषाणुओं को समाप्त करने की प्रक्रिया खाद्य विकिरण कहलाता है।

खाद्य विकिरण के अनुप्रयोग

- (i) खाद्य पदार्थों में मौजूद नकारात्मक व हानिकारक जीवाणुओं की समाप्ति
- (ii) खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में वृद्धि
- (iii) विभिन्न बीमारियों का जोखिम ~~कम~~ कम
- (iv) उत्पादन प्रक्रिया के दौरान प्रवेश ~~की~~ हुए अवशोषित जीवाणुओं की समाप्ति
- (v) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुप्रयोग
- (vi) डिब्बाबंद पदार्थों की सुरक्षा
- (vii) पेयजल को स्वच्छ बनाना

भारत के लिए महत्व.

- (i) खाद्य सुरक्षा में योगदान
- (ii) कुपोषण को कम करने में सहायक
- (iii) लोगों तक स्वच्छ ~~पेय~~ व सुरक्षित खाद्य पदार्थ पहुँचाने में सहायता

परन्तु भारत के पास इसके लिए

उपयुक्त अवसंरचना व तकनीक का अभाव है
जिसके सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता
है

8. Whereas misuse of technology has abetted the spread of fake news, it is with the aid of technology that this menace can be curbed. Elaborate.

(150 words) 10

भारत में हाल ही वातमय पर फैली अनेक झूठी खबरों के कारण विभिन्न क्षेत्रों १० लोगों की हत्या कर दी गई।

प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग व फेक न्यूज

- (i) झूठी वीडियो के साथ चेइकपाइ कर गलत संदेश प्रसारित करना
- (ii) सोशल मीडिया पर संदेश लघु गणकीय गति से प्रसारित होता है जब फेक न्यूज की सोशल मीडिया के माध्यम से तेजी से फैलाया जा सकता है।
- (iii) सोशल मीडिया पर पर्याप्त सरकारी नियंत्रण का अभाव → फेक न्यूज प्रसारित करते वालों में भ्रम का अभाव
- (iv) धुराने सभाचारों एवं सूचनाओं की तकनीकी सहायता से लोग भरोसा पेश करना

तकनीक का फेक-पूज रोकने में सहयोग

- (i) फेक-पूज को ट्रैक कर उस पर कार्रवाई करना
- (ii) फेक व असली वीडियो की तकनीक के माध्यम से जांच करना
- (iii) सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में जागरूकता का प्रसार

इस प्रकार तकनीक का फेक-पूज के प्रसार तथा निवारण दोनों में योगदान हो सकता है।

9. Explain the salient features of the recently established Defence Planning Committee. How can it help in credible defence preparedness?
(150 words) 10

रक्षा नियोजन समिति की स्थापना रक्षा उत्पादन, खरीद इत्यादि को संचालित एवं विनिश्चित करने हेतु की गई है।

रक्षा नियोजन समिति के फल

- (i) रक्षा मंत्री, ~~सैनिक~~ सैनिकों के प्रमुख व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को शामिल
- (ii) रक्षा खरीद को मंजूरी देने की शक्ति
- (iii) रक्षा के क्षेत्र में उच्च उपस्थित चुनौतियों के निवारण के संदर्भ में सलाह देना
- (iv) त्वरित निर्णय लेने में सक्षम

रक्षा नियोजन समिति का योगदान

- (i) सेवाओं को दृष्टिगत व उपकरणों को त्वरित उपलब्धता
- (ii) निर्णय लेने की गति में तीव्रता

(iii) भ्रष्टाचार में कमी

(iv) टिका खरीद में राजनीतिक हस्तक्षेप की
अनावश्यक उपस्थिति नहीं

(v) परदर्शी व कुत्ररदायी मीलामी व्यवस्था

10. Recent reports of Maoist leaders having amassed huge assets in property and cash underlines the significance of probing the funding network as part of counter-terrorism efforts. Discuss. (150 words) 10

देश के समस्त माओवादी उग्रवाद एक कठिन आन्तरिक सुरक्षा चुनौती प्रस्तुत करता है। इस उग्रवाद का वित्तपोषण इसकी प्रमुख शक्ति है जिस पर अंकुश लगाना अनिवार्य है।

माओवादी नेताओं व उग्रवादियों का निम्न स्रोतों से 'फण्डिंग' प्राप्त होती है-

- (क) फेक करेंसी का चलन
- (ख) दण्डियों की तस्करी
- (ग) मानव दुर्व्यापार तथा नशीले पदार्थों की तस्करी

हाल ही में प्रस्तुत रिपोर्ट द्वारा स्पष्टतः बताया गया है कि माओवादी नेताओं के पास विशाल मात्रा में धन संपत्ति मौजूद है। अतः इसकी समुचित जांच की आवश्यकता है।

इसके लिए निम्न कदम उठाये जा सकते हैं-

- (क) इंतेलीजेंस को सशक्त बनाना
- (ख) सीमा सुरक्षा जिसे में स्थलीय एवं जलीय सीमा दोनों शामिल हैं, को सशक्त बनाना
- (ग) सी.बी.आई. एवं 'E.D.' द्वारा इसकी समुचित जांच करवाना

चूँकि वित्तपोषण इन उद्योगों की जीवनरेखा होती है अतः इस पर शैक लगाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है ताकि भारत को आंतरिक रूप से ओर अधिक सुरक्षित बनाया जा सके।

11. Not only do services MSMEs contribute mightily to the overall GDP growth, they have a powerful, multiplier impact on the local economies as well. Elaborating on the statement, highlight the problems faced by service sector MSMEs. How can the government make it easier for MSMEs to start and grow a business? (250 words) 15

'MSME' से संबन्धित सेवा उद्यम भारत की जी.डी.पी में योगदान करने के साथ-साथ रोजगार बनाने में भी सहायक होते हैं।

इनके प्रमुख योगदान निम्नलिखित हैं-

- (क) सेवा क्षेत्र के विकास व निर्माण में योगदान
- (ख) रोजगार में वृद्धि
- (ग) छोटे शहरों में उद्यमों द्वारा उनका समुचित विकास
- (घ) क्षेत्रीय असंगतता में कमी में सहायक
- (च) स्थानीय स्तर पर लोगों के विकास में सहायक जिससे बड़े स्तर पर उद्योगों को सहायता
- (छ) ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों में 'B.P.O.' की स्थापना से उन क्षेत्रों का समुचित विकास

परन्तु वर्तमान में इन उद्यमों द्वारा आने
समस्याओं का सामना किया जा रहा जिसमें
से मुख्य समस्याएं हैं-

- (क) प्रशिक्षित व कुशल मानव श्रम की कमी, क्योंकि
ग्रामीण स्तर पर कौशल विकास का निम्न
स्तर पाया जाता है
- (ख) सरकार द्वारा की सेवा उद्यमों पर ज्यादा
भोकात व MSME की अपेक्षा
- (ग) इन उद्यमों के निर्यात संवर्धन पर बल
नहीं
- (घ) अमेरिका द्वारा संरक्षणवाद की नीति के
फलस्वरूप निर्यात में कमी

इसलिए इन उद्यमों की समस्याओं के
निराकरण हेतु निम्न कदम उठाए जाते चाहिए-

- (क) कौशल विकास को बढ़ावा देकर कुशल
मानव श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करना

(ख) उद्यम प्रारंभ करने के लिए संपूर्ण धुंजीकरण प्रक्रिया को एकल खिड़की प्रक्रिया के माध्यम से सुगम व सुगम बनाना

(ग) त्वरित व सस्ते प्रदूषण की उपलब्धता सुनिश्चित करना

(घ) इनके उद्योगों के विपणन व निर्यात हेतु उपयुक्त नीतियों एवं उद्योगों की व्यवस्था करना

धुंकी इन उद्योगों का स्थानीय एवं क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है अतः इनके विकास हेतु त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है।

12. Contract Farming has many advantages, however it suffers from market failures. Elaborate. What can the government do to correct problems that lead to contract failures? Also, discuss whether the Model Contract Farming Act, 2018 is a step in the right direction. (250 words) 15

जब किसान व क्रेता एक समझौते के तहत कृषि कार्य का संचालन करते हैं, उन्ही को संविदा कृषि की संज्ञा दी जाती है।

इसके तहत उत्पाद का क्रेता फसल को खरीदने संबंधी समझौता किसान के साथ फसल उगाने से पूर्व करता है।

इसके समक्ष निम्न बाजार चुनौतियाँ

विद्यमान हैं -

- (क) किसान अपनी फसल के मूल्य का अविद्यमानता मूल्य निकालने निकालने में पूर्णतः सक्षम नहीं होता
- (ख) इसमें मूल्य एवं उत्पाद की उपज के बारे में अनिश्चितता के कारण किसान एवं क्रेता को चुकसान उठाना पड़ सकता है।

इन समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए जा सकते हैं-

- (क) संविदा कृषि के प्रावधानों को सुस्पष्ट करना
- (ख) आनेश्चैन परिस्थितियों के समय नुकसान होने पर भुआवजे का प्रावधान करना
- (ग) संविदा की शर्तों पर विवाद होने पर उसके निपटारे हेतु 'डाचिन व्यवस्था' का निर्माण करना
- (घ) किसानों एवं क्रेताओं के मध्य जागतकता का प्रसार करना

इसी परिप्रेक्ष्य में नीति आयोग ने एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, २०१४ का विकास किया है ताकि राज्य अपनी आवश्यकतानुसार इनके अपने राज्य में लागू कर सकें। शान्त्य है कि कृषि राज्य सूची का विषय होता है।

इस आचिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं-

- (क) संबिदा की शर्तों का उल्लेख
 (ख) अनिश्चित काल में हो उठाए जाने वाले
 कार्यों का उल्लेख
 (ग) विवाद निपटारा व्यवस्था

परन्तु इनके सभी राज्यों द्वारा पर्याप्त
 स्तान्ची के साथ लागू नहीं किया जा रहा है।
 अतः इनकी सफलता के समक्ष प्रश्नचिह्न व्याप्त
 हैं।

13. Suggest the measures needed to improve the employability of labour force as well as increasing number of employment opportunities in light of structural changes being brought by disruptive technologies.

(250 words) 15

श्रम बल की नियोजनीयता में सुधार के उपाय.

- (i) कौशल विकास पर बल
- (ii) शिक्षा व्यवस्था को औद्योगिक मांग के अनुरूप बनाना
- (iii) श्रम सुधारों को बल देना
- (iv) शिक्षा व्यवस्था में शान्तिकारी सुधार व शिक्षा को रोजगारो-मुखी बनाना

रोजगार अवसरों को बढ़ाना.

- (i) उद्योगों के विकास पर बल - भेक रु संशोधन
- (ii) कु प्रदानमेगी कौशल विकास योजना
- (iii) स्वतंत्र रूप संशोधन - नवाचार में प्रोत्साहन

1068

VISION IAS™

Don't write
anything this
margin
(इस आण में
कुछ ना लिखें)

14. India's trade policy in agriculture, marred by ad-hocism and pro-consumer bias, has constrained realization of export potential, and prevented the farmers from reaping the benefits. Examine the statement and discuss ways, including government initiatives, to improve agricultural exports.

(250 words) 15

सरकार के उपाय-

- (i) e-NAM का क्रियान्वयन
- (ii) GRAMS की स्थापना
- (iii) न्यूनतम ~~की~~ समर्थन मूल्य में वृद्धि
- (iv) Model APMC एक्ट
- (v)

कृषि निर्यात

- (i) आयात शुल्क लगाना
- (ii) निर्यात सब्सिडी
- (iii)

1068

VISION IAS™

Don't write
anything this
margin
(इस भाग में
कुछ ना लिखें)

1068

VISION IAS™

Don't write
anything this
margin
(इस आंच में
कुछ ना लिखें)

15. Is currency exchange rate a suitable measure of relative economic performance of countries? Despite improving macro-economic fundamentals, trade deficit in India continues to widen. Bring out the factors responsible for this situation. (250 words) 15

एक देश की मुद्रा का किली दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष मूल्य मुद्रा विनिमय दर कहलाता है।

मुद्रा विनिमय दर के द्वारा देश की आर्थिक स्थिति का काफी हद तक ज्ञान होता है -

- हमारे देश के घरेलू उत्पाद की बिक्री का ज्ञान होता है
- देश की बैंकिंग व्यवस्था का ज्ञान होता है
- देश के वस्तु एवं सेवा उत्पादन तथा उनके आयात- निर्यात का ज्ञान भी होता है
- देश के अन्दर महंगा मुद्रास्फीति का बोध होता है

हालांकि अनेक बार अधुनात्मक परिवर्तनों के कारण मुद्रा विनिमय दर आरोपमंद नहीं होती क्योंकि यह देश के दीर्घकालिक विकास की

अस्वीकृत प्रस्तुत नहीं करती हैं। अतः देश के आर्थिक निर्यात के संकेतक के रूप में इनके पूर्वाग्रह स्वीकार नहीं किया जा सकता।

भारत ने निम्न सुधार किए हैं-

- (i) विदेशी व्यापार नीति 2015-20 का अर्थ-व्यय
- (ii) 'मेक इन इण्डिया' कार्यक्रम
- (iii) आधारगत संरचना में सुधार - निर्यात प्रोत्साहन योजना तथा निर्यात अवसरिता कार्यक्रम

इनके बावजूद व्यापार घाटे के बढ़ने के निम्न कारण हैं-

- (क) उद्योग के विकास व संवर्द्धि का अपेक्षित स्तर पर ना होना
- (ख) अनेक देशों की संरक्षणवादी संरक्षणवाद की नीतियाँ
- (ग) अवसंरचना का अपेक्षित स्तर पर ना होना
- (घ) 'मेक इन इण्डिया' का अपेक्षित स्तर पर ना होना

(च) इली के साथ भारत का चीन व अन्य देशों के उत्पादों के साथ व प्रतिस्पर्धी के कारण भी निर्यात में गिरावट आती है।

(घ) तेल के दामों में वृद्धि

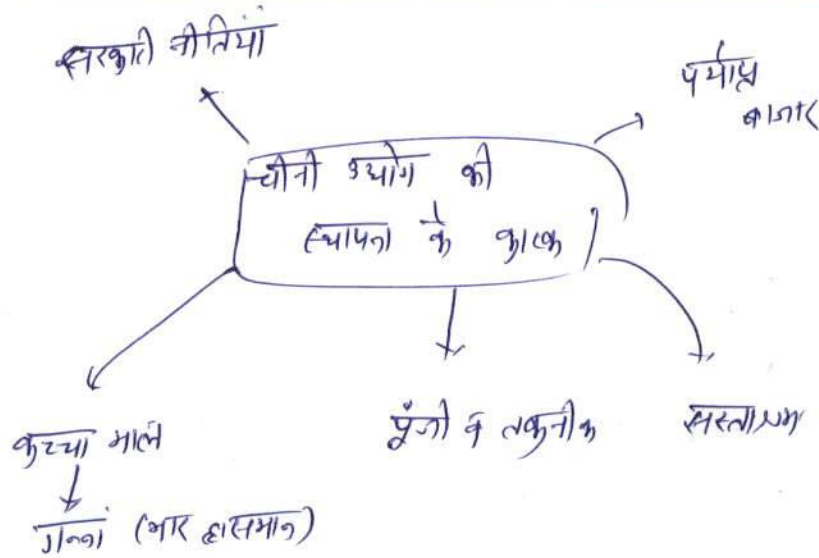
अतः उपर्युक्त सुधारों के द्वारा निर्यात में वृद्धि एवं आयात को कम करते व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिल सकती है।

16. It will take much more than relief packages to address the problems being faced by the sugar industry in India. Discuss. (250 words) 15

भारत में चीनी उद्योग एक महत्वपूर्ण
विनिर्माण उद्योग है जिसका देश की G.D.P एवं
रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान है।

परन्तु चीनी उद्योग द्वारा निम्नालिखित
समस्याओं का सामना किया जा रहा है-

- (क) कुच्चे गाल की पर्याप्त आपूर्ति में बाधा
(ख) चीनी उत्पादन की मशीनों का पुरानी मशीनों
से संचालित होने के कारण उत्पादन
कम होना
(ग) उन्नत परिवहन की व्यवस्था के अभाव
के कारण कुच्चे गाल अचिर गन्ने का
समय पर मिल पर ना पहुँचने के
कारण कम चीनी उत्पादन
(घ) चीनी बाजार की अनिश्चितता



इस क्षेत्र के विकास हेतु सरकार द्वारा

उठाएँ गये कदम निम्नलिखित हैं -

- (क) गन्ना के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि ताकि गन्ना उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके
- (ख) आधारभूत संरचना के विकास हेतु सरकार के प्रयास
- (ग) चीनी की कालाबाजारी व जमाखोरी पर रोक तथा इसे आवश्यक वस्तु के रूप में

के तहत लागू

(ध) नई उन्नत मशीनरी की स्थापना ताकि प्रति इकाई गन्ने से ज्यादा चीनी प्राप्त की जा सके

(च) कृषाल मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना - प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम

परन्तु उपर्युक्त उपायों के ~~अभाव~~

अभाव भी सरकारों की इन संवेद्य में ओर ज्यादा रुझान उठाने की आवश्यकता है ताकि नीचे उद्योग का समुचित विकास सुनिश्चित किया जा सके।

17. NAPCC, almost 10 years old and formulated with lofty objectives, has not served as the best answer to cope with the impacts of climate change. Critically discuss. (250 words) 15

जलवायु परिवर्तन को चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा २००४ में NAPCC (राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना) को प्रारंभ किया गया।

इसके अंतर्गत निम्न आठ मिशन शामिल हैं -

- (क) राष्ट्रीय हरित विकास मिशन
- (ख) सौर ऊर्जा मिशन
- (ग) जल मिशन
- (घ) हिमालयी पारिस्थितिकी संवर्धन मिशन
- (च) ज्ञान संवर्धन मिशन
- (छ) नवीकरणीय ऊर्जा मिशन
- (ज) स्वतंत्र शहरी विकास मिशन इत्यादि

उपर्युक्त मिशनों के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए

अनेक आर्थिक, सामाजिक व पारिस्थितिकीय उपायों का प्रावधान है। परन्तु अनेक कारणों से ये अपेक्षित सफलता से प्राप्त नहीं कर पाये हैं-

- (क) विज्ञान का अभाव
- (ख) कृषक मानव संसाधन का अभाव
- (ग) उन्नत प्रौद्योगिकी का अभाव ताकि उत्पाद-प्रक्रिया प्रक्रिया को जलवायु से अनुकूल बनाया जा सके
- (घ) लोगों में जागरूकता का अभाव

भारत सरकार ने पेरिस समझौते के तहत अपने 'INDC (~~Intended~~ Intended Nationally determined Contribution)' का घोषित किया है जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं-

- (क) उत्सर्जन को 2005 के स्तर से 30-35%

कम करना (2030 तक)।

(ब) 2.5 लाख गीगाटन के कार्बन सिंक का निर्माण

(ग) 2030 तक कुल ऊर्जा का 40% नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करना

अतः उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार को तुरन्त उचित उपाय करने की आवश्यकता है।

18. Proliferation of nuclear weapons and the threat of their use are key concerns for global security nonetheless existing international arrangements seem to be ineffective. Comment. Also, identify the salient features of India's policy in this context and discuss whether India should join the NPT in the current form. (250 words) 15

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु
दक्षिणों की मात्रा में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।
इसके द्वारा बार-बार परमाणु
हमले की धमकी देना तथा अनेक जैत-जिम्मेदार
देशों के पास इनकी उपस्थिति के कारण
वैश्विक शान्ति के समस्त संकट भंडारा रहा है।

परमाणु अप्रसार को रोकने के लिए
वर्तमान में व्याप्त व्यवस्थाएँ

- (i) NPT - परमाणु अप्रसार संधि (1967)
- (ii) CTBT - व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध संधि
- (iii) FTBT
- (iv) 2017 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में
संपन्न परमाणु अप्रसार समझौता

परन्तु निम्नालिखित कारणों से ये व्यवस्थाएँ
अप्रभावी सिद्ध होती प्रतीत हो रही हैं-

- (क) विकसित देशों, जिनके पास परमाणु हथियार
हैं, उनके द्वारा इनका ईमानदारी से
पालन ना करना
- (ख) इन संधियों का भेदभाव पूर्ण होना

भारत की परमाणु हथियारों के संबन्ध में नीति

- (क) भारत 'नो फर्स्ट यूज पॉलिसी' का पालन करता
है
- (ख) भारत स्वतंत्रता के बाद से ही परमाणु
अप्रसार के पक्ष में रहा है। श्री राजीव गांधी
का 1988 का UNO में संबोधन इस
संदर्भ में महत्वपूर्ण है
- (ग) भारत उतने ही हथियारों को संश्लिष्ट करता
है जिससे न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता विकसित
की जा सके।

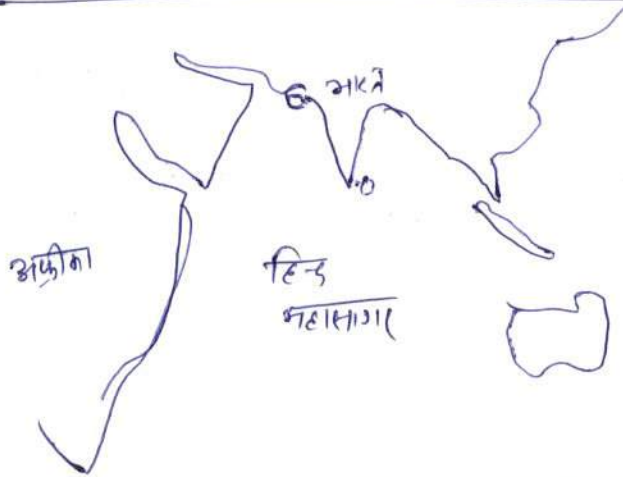
भारत का NPT में शामिल होने के संबंध
में विपक्ष में विचार

- (i) ये यह सोचेंगे अतिसावपूर्ण है तथा केवल P-5
देशों की ही परमाणु शक्ति सम्पन्न
मान्य है
- (ii) यह गैर-लोकतांत्रिक है
- (iii) भारत की संप्रभुता व सुरक्षा के विरुद्ध है

परन्तु यदि इस मामले में अपेक्षित
सुधार का हमें लोकतांत्रिक व गैर-अतिसावपूर्ण
वनाया जाता है तो भारत द्वारा इस
मामले में शामिल होने के बारे में
विचार दिया जा सकता है

19. The maritime security domain requires collective multilateral and regional cooperation to combat non traditional threats. Discuss in the context of threats in the Western Indian Ocean and the recent amendments in the Djibouti Code of Conduct. (250 words) 15

भारत के पास 7515 km लंबी समुद्री सीमा है तथा भारत हिन्द महासागर में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति रखता है अतः समुद्री सुरक्षा का भारत के लिए अत्यधिक महत्व है।



इस क्षेत्र में अनेक परंपरागत एवं गैर-परंपरागत सुरक्षा चुनौतियाँ विद्यमान हैं। पश्चिमी हिन्द महासागर में भारत के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ -

- (क) चीन का एम्बेन्टेल (श्रीलंका), स्टाइल के
बन्दरगाहों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना
- (ख) जिबूती में चीन द्वारा सैन्य बेस का
निर्माण
- (ग) भारत का अखिरसंश्लेषण तेल व्यापार
इली क्षेत्र से होना है अतः उत्तरी
क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है
- (घ) आंकी घुसपैठ - 2008 का मुंबई हमला

अतः स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में अनेक
के कारण बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय सामूहिक
प्रयासों की आवश्यकता है।

- भारत द्वारा इराक में ^{चाबहार} ~~स्काइ~~ बन्दरगाह का
निर्माण
- जिबूती के अन्वेषण क्षेत्रों में संशोधन
- इण्डियन ओशन रिम असेसिएशन की
स्थापना

→ इंडियन ओशन नैवल सिम्पोजियम द्वारा सैन्य
के आपदा प्रबन्धन अभ्यासों का आयोजन

* जिब्रती आच्छादन क्षेत्रों के संशोधन

- (i) अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत व्यापार मार्गों
का संचालन
- (ii) समुद्री सुरक्षा के खिलाफ सुरक्षा
- (iii) आतंकवाद के खिलाफ सांघिक अभियान

यहां उपर्युक्त प्रमाणों के द्वारा इस
क्षेत्र में शक्ति स्थापित करने में मदद मिल
सकती है जो भारत की ~~आर्थिक~~ सुरक्षा
सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण है।

20. India's space programme was initiated with the vision of utilising outer space for peaceful purposes, however with changing times it has the potential to play a significant role in strengthening security capabilities of India. Discuss with adequate examples. (250 words) 15

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत
INCOSPAR (Indian National Committee on Space
Research), 1962 की स्थापना के साथ मानी
जाती है। इसके पश्चात 1969 में इसरो की
स्थापना इस संबन्ध में भील का पत्थर माना
जाता है।

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लक्ष्य

- (क) भारत के आर्थिक, सामाजिक विकास में योगदान देकर उसको सशक्त बनाना
- (ख) भारत के समक्ष उपस्थित सुरक्षा चुनौतियों के निवारण का प्रयास करना
- (ग) शक्तिपूर्ण तरीकों से अंतरिक्ष का उपयोग करना
- (घ) अंतरिक्ष के संबन्ध में ज्ञान में वृद्धि करना
- (च) भारतीय नागरिकों को जागरूक व ज्ञान

से परिपूर्ण बनाना

अन्तरिक्ष कार्यक्रम की भारत की सुरक्षा को बढ़ाने में सहायता की जा सकती है इसे निम्न उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है-

- (i) नाविक (NAVIC) के द्वारा ~~समुद्री~~ समुद्री सीमाओं की सुरक्षा, भूखंडों की सुरक्षा, समुद्री व्यापार की सुरक्षा इत्यादि में सहायता मिल सकती है।
- (ii) भारतीय क्षेत्रीय (IRNSS) नौवहन सैटेलाइट प्रणाली - इसके द्वारा भारत की सीमाओं के बाहर 1500 km. तक निगरानी की जा सकती है जिससे अनेक सुरक्षा अभियानों व युद्ध के समय महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की जा सकती है।
- (iii) मिसाइलों का विकास भी ^{प्रमोचक यान} ~~प्रमोचक यान~~ (सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल) की डिजाइन व तकनीक पर आधारित होता है। भारत ने अपने

'J GMDP' कार्यक्रम के माध्यम से अनेक मिस्त्रालों का विकास किया है। इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्य हुई है

(घ) अनेक संचाल उपग्रहों के द्वारा इंटेलेजिंस की सूचनाओं की आपूर्ति

इसके अलावा भी अनेक कार्यक्रम हैं जो भारत के सामाजिक, आर्थिक विकास के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।